में "निगेटिव इंडस्ट्रीयल ग्रोथ फियर्ड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के पहले छः महीनों के दौरान औद्योगिक विकास की अनुमानित दर क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में विशेष प्रोत्साहन देकर आगामी महीनों में औद्योगिक विकास की दर में वृद्धि करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दिए जाने वाले प्रोत्साहन का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) (क) 24 दिसम्बर, 1990) के इंडियन एक्सप्रेस में "नैगेटिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ फीयर्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार में यह विचार व्यक्त किया गया है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कमी के कारण तीसरी तिमाही (अक्तूबर–दिसम्बर, 1990 में औद्योगिक विकास भी नकारात्मक हो सकता है ।

(ख) सी एस० ओ० द्वारा संकलित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार अप्रैल-सितम्बर, 1990 के दौरान कुल मिलाकर विकास दर 11.7 प्रतिशत थी।

(ग) और (घ) सरकार अधिक उदार लाइसेंस नीति बनाकर प्रक्रिया संबंधी बाधायें हटाकर तथा राजसहायता व रियायती वित्त उपलब्ध कराके औद्योगिक विकास में और गति लाने के लिए अनेक उपाय करती रही है। औद्योगिक विकास की गति को बनाए रखने के उद्देश्य से उद्योग को मूलभूत कच्चे माल की पर्याप्त एवं उचित समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

Ayodhya incident

1531. SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there was any understanding between the paramilitary forces/District Magistrate of Faizabad and the IKar-Sswaks that the Kar Sewaks should be allowed to climb the Babri Masjid; &nd

(b) what action Government have taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) No such report has been received by the Government.

(b) Does not arise.

खादी और ग्राम उद्योगों में कार्यरत कर्मकारों को यूनतम मजदूरी

1532. **श्री राम जेठमलानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 43 लाख कर्मकार खादी और ग्राम-उद्योगों में रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका का अर्जन कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस क्षेत्र में नियोजित इन कुशल और अकुशल कर्मकारों को सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है ;

(ग) यदि हां, तो सरकारी अनुमान के अनुसार खादी क्षेत्र में नियोजित कर्मकारों की वार्षिक आय क्या है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि खादी क्षेत्र में निर्मित सामान का अन्य-अन्य देशों को निर्यात किया जाता है और गत वर्षों के दौरान निर्यात में भी निरन्तर वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इन कर्मकारों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दिलाने के लिए सरकार क्या कारगर उपाय करने का विचार रखती है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजीलाल सुमन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चूंकि खादी एवं ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र के कुछ कर्मकार पूर्णकालिक आधार पर कार्य करते हैं और कुछ अंशकालिक आधार पर इसलिए खादी एवं ग्रामीण उद्योग संस्थानों द्वारा अपनाये जाने के लिए खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग ने उजरती दर के आधार पर मजदूरी की एक पद्धति निर्धारित की है, मजदूरी की राशि मजदूरी की निर्धारित उजरती दर के अनुसार कर्मकारों द्वारा किये गये कार्य पर निर्भर करती है। ग्रामीण उद्योगों के मामले में सहयोगी क्षेत्र के अधिकतम संस्थानों द्वारा दिया जाने वाला पारिश्रमिक प्रत्येक उद्योग में तथा कार्यकलाप के अनुसार अलग-अलग होता है। तथा प, ग्रामीण उद्योग में किसी शिल्पी की दैनिक औसत आय लगभग 20/–रु० (बीस रुपये) प्रति दिन है।

(घ) जी, हां। खादी क्षेत्र में उत्पादित सामान को कई देशों में निर्यात किया जाता है। वर्ष 1989–90 के दौरान के०वी०आई० उत्पाद का निर्यात बढ़कर 5.54 करोड़ रुपये का हो गया जबकि यह वर्ष 1988–89 के दौरान, 5.05 करोड़ रुपये का था।

(ङ) खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग समय-समय पर के०वी०आई० क्षेत्र में संस्थाओं द्वारा लगाये गये कर्मकारों की मजदूरी की दर की पुनरीक्षा करता है। मूल्य सूचकांक के स्तर में सामान्यतः वृद्धि के साथ-साथ मजदूरी में वृद्धि कर दी जाती है।

सन् 2025 तक सभी व्यक्तियों को रोजगार

1523. श्री राम जेटमलानी :

सरदार दलजीत सिंह अरोड़ा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2025 को उस वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है जिस तक रोजगार के इच्छुक सभी व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करा दिया जाएगा।

(ख) यदि हां, तो रोजगार के इच्छुक ऐसे युवा व्यक्तियों की अनुमानित संख्या क्या है और उस समय तक सृजित किए जाने वाले रोजगार अवसरों की अपेक्षित संख्या क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई वार्षिक योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) जी, नहीं। आठवीं योजना दृष्टिकोण दस्तावेज में परिकल्पित, 1990 के दशक की समाप्ति तक रोजगार के लिए 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की विकास दर, सन् 2000 तक लगभग पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लक्ष्य पर आधारित है। चालू दशक के दौरान इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन लोगों की संख्या जिनको रोजगार मुहैया कराना है तथा इसी तरह सृजित किए जाने के लिए अपेक्षित रोजगार अवसरों की संख्या लगभग 106 मिलियन होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं और उन्हें आठवीं योजना दस्तावेज में समाविष्ट कर लिया जाएगा।

महाराष्ट्र में गन्ने की पेराई की प्रतिष्ठापित क्षमता

1524. श्री राम जेटमलानी :

सरदार दलजीत सिंह अरोड़ा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में गन्ने की पेराई की मौजूद प्रतिष्ठापित